मंत्री 5 साल में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचें- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के अंतिम दिन विधायक दल की बैठक में सक्रिय विधायकों की सराहना की

जयपुर, 10 मार्च। मुख्यमंत्री ने 16 वीं विधानसभा के पांचवें सत्र के अंतिम दिन भाजपा विधायक दल की बैठक ली। विधानसभा के 'हां पक्ष' लॉबी में आयोजित इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सदन में सक्रिय और प्रभावी प्रदर्शन करने वाले विधायकों की सराहना करते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों को इसी तरह मजबूती से उठाते रहें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को 16 वीं विधानसभा के पांचवें सत्र के अंतिम दिन भाजपा विधायक दल की बैठक ली। विधानसभा के 'हां पक्ष' लॉबी में आयोजित इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक मौजूद थे।

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों से राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर भाग लेने का आव्हान किया।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में विधायकों के कामकाज पर लगातार नज़र रखी जाती है और जनप्रतिनिधियों पर 'तीसरी आंख' भी रहती है, इसलिए सभी को अपने व्यवहार और कार्यशैली को लेकर सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विधायकों ने जो भी मांगें रखीं, सरकार ने उन्हें पूरा करने का प्रयास किया है और आगे भी जनप्रतिनिधियों की बातों को प्राथमिकता दी जाएगी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए कि पांच साल के कार्यकाल में प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचना जरूरी है। मंत्री और जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाएं और कम से कम आठ से दस घंटे क्षेत्र में रहकर लोगों की समस्याएं सुनें और उनका समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनता से सीधा संवाद ही सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। बैठक में आगामी के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों में बढ़ -चढ़ कर भाग लेने का आव्हान किया।

'गैस के दाम बढ़ा दिए पर आपूर्ति नहीं हो रही है'

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 10 मार्च। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने मंगलवार को गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि वह गैस संकट को लेकर कुछ तथ्य छिपा रही है।

उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में तनाव का असर वैश्विक बाजारों पर पड़ना ही है, इसलिए सरकार को इससे निपटने के लिए अग्रिम तैयारी करनी चाहिए थी।

■ **कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव सचिन पायलट ने केन्द्र सरकार पर सवाल उठाया और कहा, गैस सप्लाई में कमी के लिए सरकार ने पूर्व तैयारी क्यों नहीं की।**

राजस्थान के नेता ने कहा कि सरकार ने गैस की कीमतों में वृद्धि तो कर दी, लेकिन पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की, जिसका सीधा असर आम लोगों के साथ-साथ, होटलों और रेस्तरां पर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि अगर आने वाले वर्षों में वैश्विक स्थिति ऐसी ही रहती है, तो पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। उन्होंने सरकार से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

संसद में सरकार के बयान पर उन्होंने कहा कि यह केवल एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि शांति के लिए ठोस कूटनीतिक प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं और सरकार की पहली प्राथमिकता उनके संरक्षण के लिए होनी चाहिए।

प्रदेश के पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली

बम निरोधक दस्तों व डॉग स्क्वॉड के साथ पुलिस ने सघन चैकिंग की

जयपुर, 10 मार्च। राजधानी जयपुर में मंगलवार को पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। भारत सरकार का पासपोर्ट सेवा केन्द्र (ऑर्बिट मॉल) और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जयपुर (झालाना) को ई-मेल के जरिए गैस बम से विस्फोट करने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने खुद को आईएसआई से जुड़ा बताया था।

सूचना मिलते ही, राजस्थान पुलिस, एटीएस और बम डिफ्यूज टीम मौके पर पहुंच गईं और दोनों कार्यालयों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर कार्यालयों में मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों को बाहर निकाल दिया गया तथा एंट्री अस्थायी रूप से बंद कर दी गई।

जानकारी के अनुसार, धमकी भरा ईमेल मंगलवार सुबह करीब 10 बजे मिला, जिसमें दोपहर 1:10 बजे ब्लास्ट होने की बात लिखी गई थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाही करते हुए कार्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र की जांच शुरू की। करीब एक घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

■ **एहतियात के तौर पर सभी पासपोर्ट कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई।**

फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इसे फर्जी ई-मेल मानकर जांच कर रही हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और ईमेल भेजने वाले स्रोत का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है।

इसी तरह, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, सीकर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ , डुंगरपुर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ , श्रीगंगानगर, झालावाड़, अलवर, दौसा, भरतपुर जिलों में भी पासपोर्ट कार्यालयों को धमकी का ई-मेल मिला। सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर बम निरोधक दस्तों, सिविल डिफेंस, डॉग स्क्वॉयड को बुलाया गया। हालांकि सर्च में कहीं भी संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना नहीं है।

विपक्ष ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के हमले तथा पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भी सत्र के दौरान चर्चा होने की संभावना है। इन घटनाओं के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है और कीमतें बढ़ गई हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार की नीति पर सवाल उठा सकता है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों द्वारा सदन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का मुद्दा उठाये जाने की संभावना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी शनिवार को पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से जुड़े कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन का मामला उठा सकती है। इस बीच सरकार बजट सत्र के शेष हिस्से के दौरान बिजली संशोधन विधेयक पेश कर सकती है तथा सत्र के पूर्वार्द्ध के कई लंबित विधायी कार्यों को भी ले सकती है। कार्यसूची के अनुसार, लोकसभा में चर्चा के लिए अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव ही सूचीबद्ध है।

ट्रंप ने पुतिन से लंबी वार्ता की

चर्चा है कि वार्ता ईरान जंग रूकवाने के बारे में थी

वाशिंगटन/मॉस्को, 10 मार्च। अमेरिका-इज़राइल के ईरान के साथ जारी युद्ध और मध्य पूर्व में चरम पर पहुंचे तनाव को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू होने के शुरुआती संकेत मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सैन्य अभियान शुरू होने के बाद पहली बार सोमवार रात (इंडियन स्टैंडर्ड टाइम) रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलिफोन पर लंबी बातचीत की। दोनों ने करीब साठ मिनट तक चर्चा की। कहा जा रहा है कि वार्ता का अधिकांश हिस्सा ईरान पर केंद्रित रहा। ट्रंप ने अपने समकक्ष से यूक्रेन जंग पर भी कुछ समय तक चर्चा की।

द मॉस्को टाइम्स, अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस, द वॉल स्ट्रीट जनरल और द टाइम्स (लंदन) की रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों नेताओं की वार्ता पर क्रेमलिन ने बयान भी जारी किया है। इसमें कहा गया कि सोमवार को यह वार्ता करीब एक घंटे तक चली।

पुतिन के हवाले से क्रेमलिन प्रवक्ता ने बयान में कहा कि ट्रंप ने अपने समकक्ष से ईरान युद्ध को जल्दी सुलझाने के लिए कई प्रस्ताव रखे। पुतिन ने कहा वह खाड़ी नेताओं के साथ-साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के संपर्क में हैं। क्रेमलिन ने कहा कि दोनों ने वेनेज़ुएला और ऊर्जा उद्योग के बारे में भी बात की।

■ **विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा लगता है कि ईरान वॉर रूकवाने के कूटनीतिक प्रयास शुरू हो गए हैं।**

एक रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने पुतिन से ईरान और यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की कोशिशों पर चर्चा की। एक्सियोस का आकलन है कि रूस ईरान का अहम साथी है। अमेरिकी अधिकारियों को चिंता है कि रूस इस युद्ध में ईरानियों की मदद कर रहा है। हालांकि ट्रंप ऐसा नहीं मानते पर वाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि रूस को ईरान के साथ कोई भी खुफिया सूचना नहीं बांटनी चाहिए।

पुतिन की विदेश नीति के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि दोनों के बीच बातचीत बेहद साफ और आपसी हितों पर केंद्रित रही। उन्होंने दावा किया कि पुतिन ने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप को कई प्रस्ताव दिए।

इस घटनाक्रम के बीच ईरान के उप विदेशमंत्री काजम गरीबाबादी के हवाले से एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने युद्धिवराम की शर्तों के लिए उनसे संपर्क किया है। गरीबाबादी ने ईरान के सरकारी ब्राडकॉस्टर प्रेस टीवी पर कहा कि फ्रांस, चीन और रूस ने शांति प्रस्ताव की शर्तों पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया है। गरीबाबादी की घोषणा के कई घंटे बाद ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, उनकी "पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई।"

ट्रंप ने कहा, "मैंने पुतिन से कहा कि आप मेरी युक्रेन में युद्ध खत्म कराने पर मदद लीजिए। साथ ही आप ईरान के साथ युद्ध बंद कराने में मददगार बनें।" पुतिन के करीबी उशाकोव ने यह भी कहा कि दोनों ने तेल बाजार में कीमतों में तेजी पर भी चर्चा की।

राज्यपाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आईसीयू 2 में भर्ती किया गया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर भी हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टरों के मुताबिक, राज्यपाल को यूरिन में इन्फेक्शन के साथ ही किडनी में थोड़ी समस्या को देखते हुए यहां जनरल मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी की टीम की देखरेख में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वहीं, राज्यपाल के यूरिन और ब्लड की दोबारा सैंपलिंग कराकर उन्हें टैस्टिंग के लिए भिजवाया है। राज्यपाल के ट्रीटमेंट के लिए 7 से ज्यादा डॉक्टरों की टीम का एक मेडिकल बोर्ड बनाया है। इसमें जनरल मेडिसिन, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी तथा कार्डियोलॉजी के सीनियर डॉक्टर्स है।

बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा

चंडीगढ़ , 10 मार्च। बीएसफ ने सीमा पार से हो रही तस्करी की कार्रवाई को असफल बनाते हुए, तरनतारन के खेमकरण सेक्टर में हेरोइन तस्करी का प्रयास कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढे र कर दिया। इस संबंध में पाकिस्तान को सूचित किया गया है, लेकिन वहां से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

घुसपैठ करते पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया

राजौरी, 10 मार्च। सेना के जवानों ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास घुसपैठ की कोशिश करते एक आतंकवादी को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया।

व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि खुफिया सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए, सुरक्षा बलों ने दोपहर करीब तीन बजे एलओसी के पास नौशेरा सेक्टर के झंगड़ के सामान्य इलाके में दो आतंकवादियों की गतिविधियों का पता लगाया।

■ **अवैध रूप से नियंत्रण रेखा पार करते समय सुरक्षाबलों ने उन्हें निशाना बनाया।**

गोलीबारी होने पर एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया, जिससे नियंत्रण रेखा के किसी भी उल्लंघन को प्रभावी ढ ंग से रोका जा सका। दूसरे आतंकवादी का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह इलाके में छिपा हुआ है।

'राहुल निडर हैं, बेझिझक सच बोलते हैं'

प्रियंका गांधी ने संसद में यह भी कहा कि राहुल गांधी ही एक मात्र नेता है जिन्होंने 12 साल में एक बार भी सरकार के सामने सिर नहीं झुकाया

नई दिल्ली, 10 मार्च। लोकसभा अध्यक्ष को हटाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर सवाल उठाए और प्रियंका गांधी को राहुल से बेहतर बताया। इस पर प्रियंका गांधी मुस्कुराती रहीं। इसके बाद रिजिजू ने उनके मुस्कुराने का जिक्र कर पंडित नेहरू का कथन उद्धृत किया। इस पर प्रियंका ने राहुल को निडर नेता बताया।

■ **प्रियंका ने यह टिप्पणियां तब की जब संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू ने कहा राहुल की जगह प्रियंका बेहतर नेता प्रतिपक्ष होतीं।**

रिजिजू ने अपने भाषण में कहा कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता क्यों बनाया गया, जबकि वे गंभीर नहीं हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा बेहतर विपक्ष की नेता होतीं। रिजिजू के इस बयान पर प्रियंका मुस्कुराती हुई अपनी सीट से खड़ी हो गईं।

प्रियंका ने कहा, "मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि आज उन्होंने पंडित नेहरू का कथन अपने पक्ष में इस्तेमाल किया, जिनकी वे दिन-रात आलोचना करते हैं। आज रिजिजू ने पंडित नेहरू के उस कथन का हवाला दिया जिसमें उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही थी।"

'हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं'

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने अमेरिका की कहर बरसाने की धमकी पर जवाब दिया

तेहरान/वॉशिंगटन, 10 मार्च। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के 11वें दिन तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि ईरान पर अब तक के सबसे बड़े और सबसे तीव्र हमले किए जा सकते हैं। इसके जवाब में ईरान के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि देश किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने कहा कि कोई भी ताकत ईरान को मिटा नहीं सकती। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान कम से कम छह हजार साल पुरानी सभ्यता का वारिस है और इतिहास में कई आक्रमणकारियों ने इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उनके मुताबिक जो लोग ईरान को खत्म करने का सपना देखते हैं, वे इतिहास को नहीं समझते।

■ **उन्होंने ईरान 6 हजार साल पुरानी सभ्यता है कई हमलावरों ने इसे खत्म करने की कोशिश की पर वे सफल नहीं हो सके।**

वहीं, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने भी अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरानी जनता किसी भी धमकी से नहीं डरती। उन्होंने कहा कि पहले भी कई शक्तिशाली ताकतों ने ईरान को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहीं।

लारीजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को परोक्ष संदेश देते हुए कहा कि जो लोग ईरान को मिटाने की बात कर रहे हैं, उन्हें अपने अंजाम के बारे में भी सोचना चाहिए। उनके अनुसार इतिहास गवाह है कि ईरान पर हमला करने वाले कई आक्रमणकारी समय के साथ खत्म हो गए, लेकिन ईरान कायम रहा।

पदीय कर्तव्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिसर में घुसे और दीवार और गेट को तोड़ दिया। यह कार्रवाही तत्कालीन अधिकारी के निर्देश पर हुई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन बाद में एफआर पेश कर दी। इसके खिलाफ दायर प्रोटेस्ट पिटिशन पर अदालत ने 10 फरवरी, 2010 को याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रसंज्ञान ले लिया। इसके खिलाफ दायर रिवीजन पर भी कोर्ट ने यह आदेश बहाल रखा। इसे चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया कि यह कार्रवाही सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर की गई थी और जेडीए में प्रवर्तन अधिकारी होने के कारण उन्हें इसका अधिकार था। ऐसे में उन्हें सीआरपीसी की धारा 197 के तहत संरक्षण प्राप्त है।

'होर्मुज़ स्ट्रेट रोका तो ईरान पर कहर बरसेगा'

अमेरिका ने होर्मुज़ स्ट्रेट रोकने के लिए ईरान को कड़ी चेतावनी दी

वॉशिंगटन, 10 मार्च। अमेरिका ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उसने होर्मुज़ स्ट्रेट से तेल आपूर्ति बाधित करने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि अगर ईरान इस अहम समुद्री मार्ग से तेल के प्रवाह को रोकने का प्रयास करता है, तो अमेरिका उसे कई गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा।

हेगसेथ ने कहा कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भी स्पष्ट कर दिया है कि होर्मुज़ स्ट्रेट में तेल आपूर्ति रोकने की किसी भी कोशिश का कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में ईरान पर मौत, आग और कहर बरसेगा। यह बयान उस समय आया है जब अमेरिकी सैन्य अभियान "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी" को लेकर नई जानकारी साझा की गई। इस दौरान जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन ने बताया कि अमेरिकी सेना क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षा और संभावित सैन्य विकल्पों का आकलन कर रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अब तक ईरान के मिसाइल, नौसैनिक और सैन्य ढ ांचे से जुड़े 5,000 से अधिक लक्ष्यों पर हमले किए जा चुके हैं।

■ **ज्ञातव्य है कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण है और यह मार्ग समुद्र में जहाजों के परिवहन के लिए बहुत जरूरी है।**

अपने फायदे के लिए विभिन्न देशों में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोल्ड वॉर के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका सत्ता परिवर्तन अभियानों में अधिक सक्रिय रूप से शामिल हुआ। वर्ष 1953 में, सीआईए ने ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेघ की सरकार को उखाड़ दिया, क्योंकि उन्होंने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था।

इस ऑपरेशन ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता में बहाल किया। शाह का शासन कुछ समय के लिए स्थिरता लाया और वॉशिंगटन के साथ करीबी संबंध बनाए। तानाशाही शासन और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ आक्रोश ने अंततः 1979 में इस्लामिक क्रांति का रूप लिया, जिसने राजतंत्र को इस्लामिक गणराज्य से बदल दिया और ईरान को अमेरिका के प्रमुख विरोधियों में से एक बना दिया।

वर्ष 1954 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्वाटेमाला में एक तख्तापलट को समर्थन दिया, जिसने लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति जैकोबो आर्बेन्स को उखाड़ फेंका। वॉशिंगटन उसके द्वारा किए गए भूमि सुधारों और लेफ्टिस्ट रुझानों को अमेरिका के लिये खतरा मानता था। इस तख्तापलट ने सैन्य शासन की शुरुआत की और दशकों लम्बे नागरिक संघर्ष और दमन को जन्म दिया, जिसके कारण ग्वाटेमाला राजनीतिक रूप से कई वर्षों तक अस्थिर रहा।

वर्ष 1961 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा में फिडेल कास्त्रो की सरकार को उखाड़ने का प्रयास किया, जिसे असफल बे ऑफ पिग्स आक्रमण के जरिए अंजाम दिया गया था, ऑपरेशन सीआईए द्वारा प्रशिक्षित क्यूबा के निर्वासितों ने किया था। यह ऑपरेशन न केवल विफल हो गया, बल्कि कास्त्रो की स्थिति मजबूत हुई, साथ ही क्यूबा सोवियत संघ के साथ और अधिक मजबूती से जुड़ गया, जिससे शीत युद्ध के तनावों में वृद्धि हुई।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1965 में डोमिनिकन गणराज्य में भी सैन्य हस्तक्षेप किया, ताकि वह सिविल वॉर को रोक सके वॉशिंगटन को लगता था कि यह वॉर वामपंथियों के नियंत्रण में जा रहा था। अमेरिकी सैनिकों ने एक और अधिक रूढ़िवादी सरकार की स्थापना में मदद की। हालांकि इस हस्तक्षेप ने कुछ हद तक व्यवस्था बहाल की, तथा देश में तानाशाही राजनीतिक संरचनाओं को भी लंबा किया।

वर्ष 1973 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चिली की सेना के तत्वों का समर्थन किया, जिन्होंने समाजवादी राष्ट्रपति सल्वाडोर अलेंडे की सरकार को उखाड़ फेंका। इस तख्तापलट के बाद जनरल अगस्तो पिनोचेट को सत्ता में लाया गया। पिनोचेट के शासन के तहत चिली ने राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक पुनर्गठन का अनुभव किया, लेकिन इसके साथ ही व्यापक मानवाधिकारों का उल्लंघन भी हुआ। देश अंततः 1990 में लोकतंत्र में वापस लौट आया।

वर्ष 1980 के दशक में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दो और देशों में सीधे सैन्य हस्तक्षेप किए। वर्ष 1983 में, अमेरिकी बलों ने ग्रेनेडा पर आक्रमण किया, जहां एक मार्क्सवादी सरकार के भीतर आंतरिक उथल-पुथल के बाद हुए इस हस्तक्षेप से शासक जुंटा को हटा दिया गया और चुनावों और अपेक्षाकृत स्थिर लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

वर्ष 1989 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पनामा पर आक्रमण किया, ताकि सैन्य शासक मैनुएल नोरेगा को हटाया जा सके, जो अमेरिका में ड्रग तस्करी के आरोपों में अभियुक्त थे। नोरेगा को गिरफ्तार किया गया और पनामा ने बाद में एक स्थिर लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली की ओर कदम बढ़ाया।

कोल्ड वॉर के बाद के युग में, शासन परिवर्तन युद्ध और भी विवादास्पद हो गए। 11 सितंबर के हमलों के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, तालिबान शासन को उखाड़ फेंका, जो अल-कायदा को शरण दे रहा था।

हालांकि काबुल में एक नई सरकार स्थापित की गई, लेकिन देश दो दशकों तक संघर्ष में डूबा रहा। वर्ष 2021 में अमेरिकी वापसी के बाद, तालिबान सत्ता में वापस आ गया, जिससे हस्तक्षेप की दीर्घकालिक प्रभावशीलता पर सवाल उठे।

वर्ष 2003 में इराक पर आक्रमण का उद्देश्य सद्दाम हुसैन को हटाना और कथित रूप से विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना था। सद्दाम का शासन खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद कई सालों तक विद्रोह, संप्रदायिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा, जिसमें चरमपंथी समूह का उभार हुआ। इराक ने अंततः एक निर्वाचित सरकार स्थापित की, लेकिन देश अभी भी राजनीतिक और सुरक्षा समस्याओं का सामना कर रहा है।

एक और विवादास्पद हस्तक्षेप 2011 में लीबिया में हुआ, जब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित नाटो के नेतृत्व में एक अभियान ने अरब स्प्रिंग के दौरान मुअम्मर गद्दाफी को उखाड़ फेंका। हालांकि इस हस्तक्षेप ने लंबे समय तक शासन करने वाले नेता को हटाने में सफलता प्राप्त की, लीबिया इसके बाद प्रतिद्वंद्वी मिलिशिया और प्रतिस्पर्धी सरकारों के बीच गुटीय संघर्ष में डूब गया, जिससे देश भारी अस्थिरता का शिकार हो गया।

इन घटनाओं को एक साथ देखा जाए, तो यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक लगातार बनी हुई दुविधा को दर्शाता है। सैन्य हस्तक्षेप अक्सर शासन को जल्दी हटा सकता है, लेकिन इसके बाद स्थायी राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करना कहीं अधिक जटिल है। कई मामलों में ईरान, ग्वाटेमाला, अफगानिस्तान, इराक और लीबिया से लेकर-शासन परिवर्तन के दीर्घकालिक परिणामों ने अस्थिरता पैदा की है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक भू-राजनीति को आकार देती रही है।

क्या अमेरिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रिपोर्ट में कहा गया है कि, अभियान को जारी रखने के लिए वाइट हाउस इस सप्ताह अतिरिक्त रक्षा बजट की मांग कर सकता है, जो दसियों अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, इसके साथ ही, यह भी उम्मीद की जा रही है कि इज़रायल और अमेरिका हथियारों के इस्तेमाल में बदलाव करते हुए, लेज़र-गाइडेड बमों का ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन देशों के पास ऐसे हथियारों का बड़ा भंडार है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा कि विभाग के पास राष्ट्रपति द्वारा चुने गए समय और स्थान पर किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए जरुरी, हर चीज मौजूद है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने हाल ही में तेहरान को हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) से तेल की आपूर्ति को बाधित करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "अगर ईरान ऐसा कुछ करता है, जिससे हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल का प्रवाह रुकता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका बीस गुना ज्यादा कठोरता से जवाब देगा।

उन पर मौत, आग और गुस्से की बारिश होगी। लेकिन मैं उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि ऐसा न हो।"

बंद हो सकते हैं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में संचालन संबंधी एक और झटका (ऑपरेशनल शॉक) आर्थिक रूप से कमजोर व्यवसायों को दिवालिया बना सकता है।

उद्योग के नेता सरकार से अपील कर रहे हैं कि स्थिति और बिगड़ने से पहले जल्दी हस्तक्षेप किया जाए। एक तत्काल कदम यह हो सकता है कि आतिथ्य क्षेत्र के लिए व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की "न्यूनतम सुनिश्चित आपूर्ति" पक्की की जाए, ताकि रेस्तरां अपना काम जारी रख सकें। कम जरूरी कॉमर्शियल उपभोक्ताओं से स्टॉक को कुछ समय के लिए हटाना, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और वितरकों के बीच बेहतर तालमेल, और प्रभावित शहरों तक तेज़ आपूर्ति व्यवस्था करना, दबाव कम करने में मदद कर सकता है। लंबे समय में यह संकट इस बात को भी उजागर करता है कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में व्यवधान आने पर आतिथ्य क्षेत्र कितना असुरक्षित है। नीति-निर्माताओं को बड़े शहरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) नेटवर्क का विस्तार तेज़ करना पड़ सकता है और व्यावसायिक रसोइयों को ईंधन के अलग-अलग स्रोत अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, ताकि वे पूरी तरह एलपीजी पर निर्भर न रहें। अभी के लिए समस्या बहुत बड़ी और तात्कालिक है। यदि व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति जल्द स्थिर नहीं हुई, तो कई रेस्तरां की रसोइयां बंद करनी पड़ सकती हैं। पश्चिम एशिया में शुरू हुआ संघर्ष अब भारत के शहरों में भी असर दिखाने लगा है, बिलकुल वहीं, जहां देश खाना बनाता है और खाता है।

जिष्णु देव वर्मा ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नार्वेकर, विधान परिषद की उपसभापति डॉ.नीलम गोऱ्हे, पूर्व मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ ा, मुंबई नगर निगम के आयुक्त भूषण गगराणी, पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, मुख्य राज्य शिष्टाचार अधिकारी राजेश गवांदे सहित, अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालयः** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालयः** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालयः**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908